



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 वैशाख 1945 (श0)

(सं0 पटना 391) पटना, शुक्रवार, 12 मई 2023

गृह विभाग
अभियोजन निदेशालय

अधिसूचना
10 मई 2023

सं० अ0नि0 (14) 04/2016 आरोप-1102—श्री सुरेश कुमार, तत्कालीन प्रभारी जिला अभियोजन पदाधिकारी, शेखपुरा सम्प्रति सेवानिवृत्त को श्री संजीव कुमार, जिला भ्रष्टाचार मुक्तिमोर्चा के सदस्य का अभ्यावेदन दिनांक 20.04.2016 के द्वारा कार्यालय में आम लोगों से पैसा का लेन-देन करने के लगाये गये आरोप के साथ संलग्न सी0डी0 क्लीप्स के समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक 862 दिनांक 12.07.2016 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए इनके विरुद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1298 दिनांक 23.12.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही आरम्भ किया गया तथा उक्त विभागीय कार्यवाही का संचालन पदाधिकारी संयुक्त आयुक्त (विभागीय जाँच) मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर को नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी-सह-संयुक्त आयुक्त (विभागीय जाँच) मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर का पत्रांक 366 दिनांक 01.02.2018 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। विभागीय स्तर पर जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त पाया गया कि विभागीय कार्यवाही में आरोप मुक्त करने के सम्बन्ध में संचालन पदाधिकारी द्वारा कोई प्रमाणिक तथ्य समर्पित नहीं किया गया है तथा सी0डी0 क्लीपिंग का बिना अवलोकन किये ही निष्कर्ष प्रतिवेदित किया गया प्रतीत होता है। फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-18(2) के प्रावधान के आलोक में विभागीय पत्रांक 847 दिनांक 21.05.2018 द्वारा जाँच प्रतिवेदन अनुलग्नक सहित वापस करते हुए त्रुटियों का परिमार्जन कर अपने मंतव्य के साथ जाँच प्रतिवेदन पुनः विभाग को समर्पित करने हेतु संचालन पदाधिकारी-सह-संयुक्त आयुक्त (विभागीय जाँच) मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर को निदेशित किया गया।

संयुक्त आयुक्त (विभागीय जाँच) मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर के पत्रांक 4115 दिनांक 27.07.2018 द्वारा त्रुटियों का निराकरण कर जाँच प्रतिवेदन पुनः विभाग को प्राप्त कराया गया। जाँच प्रतिवेदन में श्री कुमार के विरुद्ध कार्यालय में आम लोगों से पैसा का लेन-देन करने का प्रपत्र-‘क’ के आरोप को प्रमाणित पाया गया। फलतः संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर किये जाने के उपरान्त जाँच प्रतिवेदन से सहमत होकर श्री कुमार को विभागीय पत्रांक 1663 दिनांक 31.08.2018 एवं पत्रांक 2242 दिनांक 17.12.2018 द्वारा

संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए लिखित अभ्यावेदन या निवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

उक्त विभागीय कार्यवाही के निष्पादन के पूर्व दिनांक 31.08.2018 को श्री सुरेश कुमार के वार्धक्य सेवानिवृत्ति के पश्चात् विभागीय कार्यालय आदेश संख्या 103/2018-सह-पठित ज्ञापांक 1923 दिनांक 11.10.2018 द्वारा श्री कुमार को दिनांक 31.08.2018 के प्रभाव से निलंबन मुक्त करते हुए पूर्व संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43बी0 में परिवर्तित किया गया तथा सेवानिवृत्ति के पूर्व की तिथि/निलंबन अवधि (दिनांक 12.07.2016 से 31.08.2018 तक) के सम्बन्ध में आदेश दिया गया कि श्री कुमार को उक्त अवधि का भुगतेय वेतन/भत्ता का निर्णय विभागीय कार्यवाही के परिणाम पर आधारित होगा।

श्री कुमार के निजी पत्रांक 20 दिनांक 18.12.2018 द्वारा गठित आरोप के बचाव में यह प्रतिवेदित किया गया कि कथित आरोप एक साजिश है और मुझे कार्य के प्रति निष्ठा का ईनाम दिया गया है। कथित आरोप का किसी ने भी समर्थन नहीं किया और न ही गवाही दी। यह कार्यवाही सिर्फ मुझको प्रताड़ित, आर्थिक, नैतिक एवं सामाजिक स्तर पर बदनाम करने के लिए किया गया है। यह मामला सफेद झूठ है।

श्री सुरेश कुमार, तत्कालीन प्रभारी जिला अभियोजन पदाधिकारी, शेखपुरा सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा समर्पित लिखित अभ्यावेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर किया गया तथा पाया गया कि श्री संजीव कुमार द्वारा उपलब्ध कराये गये विडियो क्लिप्स से सम्बन्धित सी0डी0 की प्रमाणिकता की फॉरेन्सिक जाँच के सम्बन्ध में कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। श्री कुमार के विरुद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही में अंतिम निर्णय लेने से पूर्व उपलब्ध करायी गयी सी0डी0 की प्रमाणिकता की जाँच किया जाना आवश्यक है, क्योंकि सी0डी0 की प्रमाणिकता की जाँच किये बगैर श्री कुमार के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया जाना विधि सम्मत नहीं होगा। फलस्वरूप विभागीय पत्रांक 1048 दिनांक 30.05.2019 द्वारा राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला से सी0डी0 क्लिप्स की प्रमाणिकता की फॉरेन्सिक जाँच कराने हेतु अनुरोध किया गया। विधि विज्ञान प्रयोगशाला, बिहार, पटना के पत्रांक 1354/गो0 दिनांक 28.04.2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि "Video clip of exhibit mark-A has not been tampered".

संचालन पदाधिकारी के मंतव्य, आरोपी पदाधिकारी के लिखित अभ्यावेदन एवं विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा सी0डी0 की प्रमाणिकता के संदर्भ में उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन की समीक्षोपरान्त आरोपी पदाधिकारी को प्रतिवेदित आरोपों के लिए दोषी पाते हुए बिहार पेंशन नियमावली-1950 के नियम-43(ख) के तहत अनुशासनिक प्राधिकार से अनुमोदनोपरान्त "05 (पाँच) वर्षों तक 20 प्रतिशत पेंशन की कटौती" का दण्ड अधिरोपित किया गया। प्रस्तावित दण्ड के बिन्दु पर बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 5118 दिनांक 24.03.2023 द्वारा सहमति प्राप्त है।

अतः श्री सुरेश कुमार, तत्कालीन प्रभारी जिला अभियोजन पदाधिकारी, शेखपुरा सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1298 दिनांक 23.12.2016 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही में अधिसूचना निर्गत की तिथि से "05 (पाँच) वर्षों तक 20 प्रतिशत पेंशन की कटौती" का दण्ड अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही को निष्पादित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुधांशु कुमार चौबे,
उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 391-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>